[श्री सुशील चन्द मोहन्ता]

आप इनको इलैक्ट्रिफाई करने की सोच रहे है तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री बंसी लाल : वाइस चेयरमैन महोदय, देखा जाय तो जो सवाल उठाये गये हैं उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन फिर भी जैसा कि यादव जी ने खाने पीने की चीजों के बारे में कहा मैं मानता हूं कि बहुत-सी सब-स्टैन्डर्ड चीजें मिलती हैं । हम पूरी कोशिश कर रहे है कि खाने पीने की चीजें अच्छी मिलें और भगवान ने चाहा तो इसमें हमें कामयाबी मिलेगी । दूसरी बात उन्होंने स्टाफ के व्यवहार के बारे में कही है । जहां से भी हमारे पास स्टाफ के व्यवहार के बारे में शिकायतें आती हैं उस पर हम पूरा एक्शन लेते हैं । हमने एक ड्राइव भी चलाई थी कि कस्टमर के साथ करटियस व्यवहार किया जाय और अच्छी तरह से सोच-समझ कर नम्रतापूर्वक बात की जाय । अगर किसी जगह इसमें कोताही पाई जायगी तो मैं ओनरेबल मेम्बरान से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे नोटिस में लायें कि यहां पर अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है । हम उस पर फौरन एक्शन लेंगे । श्री मोहन्ता जी ने कहा कि क्या हरियाणा के आस-पास या उस तरफ जो लाइनें जाती हैं उनको इलैक्ट्रिफाई करने की योजना है । मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है । जहां तक मिश्र जी का सवाल है उन्होंने कई बातें इकट्ठी कहीं । उनका जवाब हम उनको लिखकर भेज देंगे । बाकी अगर किसी आनरेबल मेम्बर की किसी बात का जवाब नहीं दिया गया है तो उन सब बातों का जवाब हम उनको लिखकर भेज देंगे ।

The question was put and the motion was adopted.

THE TERRORIST AFFECTED AREAS (SPECIAL COURTS) AMENDMENT BILL, 1985

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF INDUSTRY, COMPANY AFFAIRS AND HOME AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act was enacted by the Parliament on 31st August 1984 replacing the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Ordinance, 1984, which was promulgated on 14-7-84. This legislation was enacted to provide for speedy trial of certain offences in terrorist affected areas against the background of terror and violence which had made functioning of the ordinary courts for trial of offences, usually committed by terrorists, extremely difficult.

As hon. Members are aware, Memorandum of Settlement between the Government and the President, Shiromani Akali Dal, provides that Special Courts constituted under the Act will try only cases relating to offences of waging war and hijacking. The Bill seeks to restrict the operation of the Act by keeping only very serious offences relating to waging war (Sections 121 121A, 122 and 123 IPC) and hijacking (Sections 4 and 5 of the Anti-Hijacking Act) within the ambit of the Act, so that only these offences could remain triable by the Special Courts and cases relating to all other offences, whether pending before the Special Courts or under investigation could become triable by ordinary Courts.

I commend the Bill to the honourable House.

The question was proposed.

SHRI K. MOHANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad that this Bill itself is a development of the Punjab Accord. Even at the time of discussion of the original Act, my party expressed its concern, and our objection to this type of legislation—even at this stage we have made it

clear—was that this type of legislation would not help to contain the terrorists and divisive activities in the country. A solution to the political problems and political demands of the people is a political settlement. This was our stand. And still it is our stand. And this Bill itself establishes that this type of draconian laws will not be the answer to the political demands of the people, and it is only through political negotiations and settlement.

Sir, the Central Government in recent years has enacted a number of this type of laws and armed itself with many arbitrary powers in the name of containing the terrorists and divisive activities. Yet, has the Government been able to contain these activities? The answer is 'no'. This Bill is a continuation of the Prevention of Terrorist and Disruptive Activities Act, which shows scant respect to the Fundamental Rights guaranteed by our Constitution itself. According to the original Act, trials under the Act will be conducted by Special Courts. The Special Courts can be appointed by the Government in consultation with or in concurrence with the Chief Justice of the High Court. Then a Public Prosecutor will be appointed by the State Governments, and the Special Court can take cognizance of an offence on receiving a complaint or on the basis of a police report, and the accused need not be committed to it for trial. These are the clauses included in the original Act. And the trial itself will be held in camera, in a protected place most probably in a prison or some place like that. And above all, even the Evidence Act does not apply in certain cases. Can we call this as a trial or a fair trial? But, Sir, even by acquiring this type of enormous power the Government has failed to contain the terrorist activities and the divisive forces in the country. Not only that, Sir. According to this original Act, the chances of misusing these powers is also there. This power has been misused to harass people who organised an agitation against the unbearable tax burden on the people or a trade union movement. People who wage a trade union struggle can be hauled up under the original Act.

Anyhow, Sir, this is a welcome development. I welcome this amending Bill. In the Statement of Objects and Reasons itself it has been stated "that in the changed situation, it is felt that it would be adequate and would be in the public interest if the jurisdiction of the Special Courts under the Act is restricted to extremely serious offences of waging war and hijacking." I am thannkful to the Government. The situation has changed. It is a fact. But how the situation has changed? Do you think that it is through the implementation of your new laws, your new legislations, new draconian Acts passed by you in the name of containing terrorism? No. The situation has been changed through political negotiations and settlement. I do hope that the Government will learn something from this.

With these words, Sir, I once again welcome this Bill.

श्री हक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक था और जितना व्यापक रूप मे था सरकार उसी की सीमायें कुछ कम कर रही है। इस रूप में बहुत से माननीय सदस्य और लोग सरकार को धन्यवाद देंगे और बिल का समर्थन करेंगे लेकिन मेरे जैसे आदमी को इससे कोई ज्यादा खुशी नहीं है क्योंकि हम दुनिया देख चुके है । इसलिये मैं इस विन्दु को उठाना चाहता हूं। पंजाब मे जो राष्ट्रविरोधी काम हुये, जो उत्पात हुये, आतंकवादी काम हुये आपने उनको नियंत्रित करने के लिए उस पर काबू पाने के लिये एक विधेयक बनाया । उसके अन्दर सारी चीजों को रख दिया लेकिन मूल रूप से सवाल यह पैदा होता है कि सामान्य कानून और विधि व्यवस्था स्थापित करने मे सरकार जब अक्षम हो जाती है तभी सरकार कोई विशेषाधिकार अपने हाथ में लेती है तो इसके बाद सरकार की अक्षमता तो निश्चित है ही सरकार अक्षम

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

हो गई, सरकार असफल हो गई। दूसरे रूप में यों कहिये इसमें अगर विस्तार रूप से जाने है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आतंकवाद के नाम पर, समाज विरोधी के नाम पर किसके सीने पर गोली लगती है ? समाज के अन्दर जो सबसे कमजोर तबका है, हजारों-लाखों, करोड़ों वर्षों से जिन्हें दबा कर के रखा गया है वह अगर अपने मानवीय अधिकार मागते हैं तो उसको उठा कर सड़क पर ले जाकर सीने पर गोली पुलिस मार देती है और दूसरे रोज ही अखबार में छप जाता है कि पुलिस का मुकाबला करते हुये इतने लोग मारे गये। इसको करने वाला कौन है ? हम कोई कानून जब बनाते है, संसद में पारित करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वह मशा साफ रहती है, सरकार की मंशा भले ही अच्छी रहती हो, लेकिन जो उसको लागू करने वाले है, जो उसको अमल में लाने वाले होते है, उनकी दृष्टि क्या होती है ? और इसलिये मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब आतंकवाद के बारे में कानून बनाते है और आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि असली आतंकवादी कौन, समाज के अन्दर असली आतंकवादी कौन ?

पंजाब के अन्दर एक विशेष परिस्थिति थी। पंजाब के अन्दर एक विशेष सवाल पैदा हुआ। वहा समझौता भी किया आतंकवाद को हटाया भी। उसमें भी बंटवारा हो गया, फिर उसमें भी बंटवारा हो गया। तो आपने जो समझौता किया भी, उस समझौते का पूर्णरूपेण पालन पंजाब के जो तमाम सिख भाई है, वह करेंगे या नही, लेकिन हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि कभी हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था जिसको आज डिसटर्ब्ड इलाका कहा जा रहा है, वहां अगर कोई किसी को मार देता था, आपस में किसी का झगड़ा हुआ, कोई किसी का खून कर दे, तो लिख दिया जाता था कि नक्सलाईट ने इनकी हत्या कर दी। मतलब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाती है।

आप टेरोरिस्ट कानून बनाइयेगा, जैसे दिल्ली मे एक कांड हुआ, ललित माकन की हत्या हुई। क्या पुलिस वाले कह रहे हैं ? टेरोरिस्ट--मतलब इसके नाम पर बच जाओ। ललित माकन की हत्या हो गई। यह सरकार की असफलता है, अक्षमता है, यह सरकार की कमजोरी है, यह सरकार नपुंसक है जहां इस तरह से किसी की हत्या हो गई, नहीं पकड़े गए कह दिया टेरोरिस्ट ने मार दिया। आप अपनी पुलिस के हाथ में ऐसे हथियार दे रहे है, कि कही पर किसी की हत्या हो जाए, कोई भी अपराध हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस सीधी कहेगी कि टेरोरिस्ट ने किया। टेरोरिस्ट का मतलब कि पुलिस पकड़ने मे अक्षम है, वह कही भाग गये, कहीं विदेश भाग गया कि कही भाग गया।

तो सामान्य रूप से जब विधि-व्यवस्था को लागू करने मे सरकार अक्षम हो जाए, तो सरकार उस विशेष अधिकार को अपने हाथ में लेती है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है।

अंतिम बात, आखिर मे मैं निवेदन करुगा, आरिफ साहब, कि टेरोरिस्ट कौन ? मै एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप नोट कर लीजिए कागज पर। बिहार प्रदेश का दरभंगा जिला जहां मैंने जन्म लिया है, मेरे घर से दो किलो-मीटर की दूरी पर डीहबेरई-गांव मे 30 जुलाई, आठ बजे दिन, चार सौ आदमी हरबे हथियार से लैस और पांच मुसलमानों का घर लूट लिया। 30 जुलाई, आठ बजे दिन, चार सौ आदमी गोली, बंदूक, बारूद से लैस होकर डीहबेरई-गांव के पांच मुसलमानों का सब कुछ लूट लिया, उनकी रोटी और सना हुआ आटा जो उनकी रोटी पकाने के लिए तैयार था वह भी उठा कर भाग गये और आज भी जब मैं इस समय सदन में बोल रहा हू आज तक एक भी आदमी को न तो गिरफ्तार किया गया है न पकड़ा गया है, न कुड़की हुई है, न जब्ती हुई है, न कुछ कार्यवाही। बताइये, यह तो एक सामान्य कानून आई०पी०सी०, सी०आर०पी०सी० के अन्दर आता है। तो सरकार की

अक्षमता तो इसी में है कि कुछ टेरोरिस्ट के नाम पर कुछ अपराध को दबा दो, कुछ अपराध सामान्य रूप से नहीं हो रहा है, आंख से अपराध को देख रहे हो, दर्न में आता है हरबे हथियार से लैस होकर आता है, पांच मुसलमानों के घर-द्वार, कपड़ा-लत्ता सब लुट कर भ.ग जाता है । उसको कुछ इन्साफ नहीं मिलता है, कहां उसे इन्साफ मिलेगा ? मजबूर होकर मुझे संसद में बोलना पड़ा । मेरे घर से दो किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी है और मेरे आसपास के, मेरे गाव के लोगों ने जब नहीं देखा गया, तो यह लोग जब प्रोटैक्शन मे खड़े हुए, तो जाकर वह लूटने वाले भागे हैं ।

बताइये, वह पब्लिक जब रोकने के लिए गई, तब वह भागे । सरकार कहा है, पुलिस कहां है ? कानून -विधि की व्यवस्था यही कहती है कि जो पुलिस का अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने मे अक्षम साबित हुआ है, उनकी वर्दी उतरवा लीजिए, उनके ऊपर मुकदमे करिये, उनको जेल भेज दीजिए, जो इस देश के हरिजन, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग की रक्षा करने में अपने कर्तव्य का निवहन नहीं कर पा रहे है।

तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विशेष अधिकार को हाथ में मत लीजिए । अपने जो सामान्य अधिकार है, उसी का पालन करवा दीजिए । आपकी पुलिस और प्रशासन अगर आई०पी०सी० और सी०आर०पी०सी० के कानून को ही मजबूती से लागू कर दें, तो सरकार को कोई विशेष कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री प्यारे लाल खडेलवाल (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष, जी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण चाहूगा । जब 31 अगस्त, 1984 को यह विधेयक इस सदन ने पास किया उस समय सभी दलों ने एक मत से इस विधेयक का समर्थन किया था। देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थीं कि जिसके कारण देश के समस्त राजनीतिक दल जिसमें मेरा दल भी सम्मिलित है, ने इस कानून का तहेदिल से समर्थन किया था । लेकिन उस समय शका व्यक्त की गई थी कि कानून लाने से ही यह सारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि यह समस्या राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक समस्या का समाधान केवल कानून से ही नहीं हो सकता, शायद तात्कालिक लाभ मिल जाये परन्तु इस समस्या का समाधान तो राजनीतिक आधार पर ही किया जाना चाहिए । उस समय सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने बहुत जोर से कहा था कि कानून ही इस समस्या का समाधान होगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हू कि आज भी जालंधर में एक भूतपूर्व कांग्रेस के विधायक श्री सैनी को गोली मार दी गई । इसके कुछ दिन पहले दिल्ली में श्री ललित माकन, जो कि लोक सभा के सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी गई ; आतंकवाद कानून से नहीं दबता । आतंकवाद जो राजनीतिक तौर पर पनपा था, पजाब मे आतंकवाद राजनीतिक तौर पर पनपा था । मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हू, पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया था कि वहां पर कि उन्होंने गुरबिन्द्र सिंह को शरण दी थी । मुझे पता नहीं यह कहां तक सच है ? सरकार इस सब की जांच कराये । आतंकवाद जो पनपा था उसके पीछे क्या कारण था ? शायद राजनीतिक कारण होगा ? लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार वापस लौटकर उसी बात पर आ गई है कि राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीतिक चर्चा से हो सकता है और इसलिए जो नया संशोधन आया है, इसमें आपने कुछ सीमित दायरा रखा है, हवाई जहाज का अपहरण और युद्ध जैसी बातें करने वालों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । मैं एक बात और कहना चाहता हू कि अभी भी सरकार ने इस कानून को बद कमरे में चलाने का फैसला किया है । इस कानून के अंतर्गत जिनपर मुकदमें चलेंगे, मैं समझता हूं कि यह न्याय प्रणाली के सिद्धांत के विपरीत है। कोई जरूरत नहीं है, आप इसको खुले में

[श्री प्यारेलाल खंडेलवाल]

चलाइये, यदि कोई अपराधी है तो वह सामने आयेगा । ठीक है, कुछ विशेष व्यवस्थाएं बना दें लेकिन इसको खुले न्यायालय में चलने दीजिए । एक बात और कहना चाहता हूं कि इस कानून को बने एक वर्ष हो गया, सरकार इस बात को बताए कि इस एक वर्ष में कितने लोगों को इस कानून के तहत पकड़ा गया, कितने लोगों को इसके अंतर्गत सजा हुई? कितने निर्दोष लोग इस कानून के अंतर्गत पकड़े गए ? ये सारी बातें, ये सारी जानकारियां सरकार को इस सदन में देनी चाहिएं । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश में कानून और व्यवस्था बिगड़ी है । केवल आतंकवाद की ही बात नहीं है, कानून और व्यवस्था वैसे भी देश में बिगड़ती जा रही है और सरकारी मशीनरी इस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है । जैसे मैंने कहा कि जालंधर के अन्दर एक व्यक्ति की दिन-दिहाड़े हत्या कर दी गई और दूसरे की हालत खराब है । पता नहीं उसकी क्या स्थिति होगी ? भगवान उसको दीर्घायु दे । आज यह स्थिति बनती जा रही है । मैं चाहता हूं कि सरकार कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सरकारी मशीनरी को चुस्त करे । सरकारी मशीनरी में जो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इसको हर स्तर पर रोका जाना चाहिए । अगर हम इस देश में कानून-व्यवस्था को ठीक से रखना चाहते हैं तो सरकारी मशीनरी को जहां चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है वहां उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी रोकने की आवश्यकता है । इन बातों के साथ मैं फिर से एक बार इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI SUSHIL CHAND MOHANTA (Haryana): Sir, I am happy that some amount of realisation has dawned upon the Government that a Bill of this nature, a Bill providing for special courts to contain terrorism, serves no purpose. It has served no purpose. The problem in Punjab has been solved not because of the powers given to the courts to try the terrorists under the special courts but the problem in Punjab has been solved because it was realised by the Government that negotiation was the way by which things could improve. I am happy. the situation in Punjab is fast returning to normalcy. But I would like to ask two pertinent questions. One is, when a person who has committed an offence of murder or dacoity, he is challenged, is apprehended under the relevant provisions of the Panel Code. But when a person commits an offence of murder runs away, is not apprehended and his whereabouts, his description and his identity is not established, then it is very easy for the police to call it an act of terrorism, to put it on a terrorist. Who is a terrorist?. I would like to know from the hon. Minister, who is a terrorist? I would like to know whether the dacoits living in the Vindhyachal region, when they commit dacoity and when they are confronted by the police party, they exchange bullets. in which a number of constables, police personnel and citizens are killed, do they fall within this definition of terrorism? My question is, will they be proceeded against under this Act; will these special powers be used against them? Or, will they be dealt with under the ordinary law? If the dacoits, for long, who have committed heinous crimes, if they have been, for long, dealt with under the ordinary law, and when it was conceded that the ordinary law was sufficient to deal with them, then, why is it that such an Act, a special Act, is needed; why should there be special courts for dealing with terrorism, when you do not know, because you do not know, who is a terrorist. When you do not know the identity of a person, you call him a terrorist.

For instance, as was pointed out by my friend, Mr. Hukumdeo Narayan Yadav, in regard to the murder of Mr. Lalit Maken—this was a heinous murder—the police have not been able to make any head or tail about the offender. They do not know whether it was due to enmity, whether it was an act of terrorism or whether it was done by persons who are known to be habitual offenders. They do not know who is the person behind this murder. Without all these things, some photos are flashed in the newspapers saying that the identity of the killer is akin to the one flashed in the newspapers indicating that probably, this was an act of terrorism. When you do not know the identity of the person who has committed an offence, when you just attribute this to a terrorist, I would say, an Act of this type does not serve anybody. The present law, the present courts are sufficient provided your detecting machinery, your enforcing machinery, is disciplined, efficient and is able to keep a track of the culprit. If the culprit can be tracked, I can assure you, the present laws are so stringent that it is very difficult for a person to escape from the purview of such laws. But if you do not know the offender and you merely attribute it to terrorism, then, you may have a special Act, you may have anything, but it will be of no avail.

In any case, I am happy, you have at least realised now that the jurisdiction of the special courts should be limited only to particular types, special types of offences. Yet, I would like to ask this question. Do the dacoits who commit dacoities and who exchange fire with the police personnel or the Border Security Force or any other force when they are confronted by them, or do the smugglers who come from across the border and exchange fire with the police when they are challenged by them, fall within the definition of the offences given in the Schedule? If they do not fall within this definition, then, what is the use of having these special courts? There is no need at all for these special courts in that case. Thank you, Sir.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, the present amendment, the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Amendment Bill, 1985, is the direct result of the accord which was reached between the Prime Minister and the Akali Dal Chief Shri Harchand Singh Longowal. I fail to understand why the Government could not visualise that in the coming days such accord would be reached. Instead, the Government allowed the situation to deteriorate. The result was chaos and confusion not only in Punjab, but in various parts of the country as well. The whole country seemed to be faced with such a situation as if something terrible is going to happen in the country. That has been allowed to continue to this day. I also fail to understand another thing. Many murders have taken place in daylight. Innocent people have been caught. But I do not know whether those who are the real culprits have been caught. Lala Jagat Narain has been killed; his son has been killed; and one hon. Member of our House has been killed in daylight. Similarly, recently a Lok Sabha Member, Shri Maken and his wife, were killed. So far no one has been caught. It has been reported in the press that some three or four persons have been detected and arrested. I do not know whether they are the real culprits. If the Special Courts are to try those people who are innocent, what will be the fate? The question is, the real culprits should be caught. Simply enactment of laws will not help. Of course, I welcome this amendment. At last wisdom has dawned on the Government and I welcome it. But the question is whether we are here simply to pass laws without implementing them. During all these days I would like to know, how many people who were the real culprits have been caught or punished? Every time we read, "so and so is killed and the police are investigating". But there are no results. So the main question is, we have to be vigilant, we have to be very

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

careful in dealing with the situation. Such a situation has arisen. We have seen how our late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, was killed in her own house. Government could not even protect her life. I do not think the situation will improve by passing this Bill. Even the original Act itself was not necessary. When I met Sant Longowal, one of his conditions was abolition of the Special Courts. And I think it is as a result of one of the demands that the present amendment has come. It is good. But I would like to know from the Government whether they are serious enough to deal with the situation.

The situation in Punjab deteriorated. There was loss of life and property. Similarly in Assam and Gujarat. Of course, agreement was reached in Assam and Gujarat. But why did we allow the situation to deteriorate to such an extent? On the whole the people will come to the conclusion that all these things are allowed to happen and later on an accord or agreement is reached only for the benefit of the ruling party. Such an impression has been created in the minds of the people. Whichever party may be in power, they must protect the safety, integrity, security and unity of the whole country, of the whole nation. That must be our aim. With that aim we have to pass laws, we have to act, and I think the Government will ponder over these things and act properly. Thank you.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदय, यह आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) संशोधन विधेयक एक खास पृष्ठभूमि में पास किया गया था । यह कानून तब पास हुआ था जब पंजाब के अंदर आतंकवादी कार्यवाहियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लोगों की हत्यायें हो रही थीं । पुल उड़ाये जा रहे थे और कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी गड़बड़ी आ गई थी । उस पृष्ठभूमि में यह कानून पास किया गया था । लेकिन अब पृष्ठभूमि बदल गई है । पृष्ठभूमि इस मायने में बदल गई है कि अब पंजाब में एक राजनीतिक समझौता हो गया है और सितम्बर माह में वहां चुनाव होंगे और एक जनतांत्रिक सरकार की स्थापना पंजाब में होगी । ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए यह था कि इस कानून को वापस ले लेती । लेकिन सरकार ने ऐसा न करके इस कानून की धाराओं को सीमित कर संशोधित रूप में पेश किया है । दो कानूनों की धाराएं इस कानून में शामिल करने की कोशिश की गई है । इंडियन पीनल कोड की धारा 121, 121ए, 122 और 123 तथा दूसरी ऐंटी हाइजैकिंग ऐक्ट की धाराएं इस कानून के अन्दर शामिल करने की कोशिश की गई है । मंत्री जी ने बोलते हुए यह कहा कि यह इसलिए हमको करना पड़ता है कि स्पीडी ट्रायल हो । स्पीडी ट्रायल एकमात्र उद्देश्य है इस कानून को रखने का । क्या यह बात सही नहीं है कि स्पीडी ट्रायल इसलिए नहीं होता कि इस तरह के कानून नहीं हैं ? अभी इसी सदन में कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि देश की कचहरियों में लाखों की संख्या में केसेज़ लंबित है और केसेज लंबित रहने का कारण यह है कि कचहरियों में केसों का फैसला करने के लिए उचित संख्या में जज नहीं है । इसलिए केसेज कचहरियों में पड़े हुए हैं, इसलिए उनका फैसला नहीं होता । मेरी समझ यह है कि ऐंटी हाइजैकिंग की जिस धारा का तथा इंडियन पीनल कोड की जिन चार धाराओं को इसमें रखने की कोशिश की गई है, वे धाराएं उन्हीं कानूनों के दायरे के अन्दर आती है, अगर कोई इस तरह का जुर्म करे और अपराध करे तो उनको उसी जुर्म में दंडित किया जा सकता है । अगर कोई आदमी देश के विरुद्ध जुर्म करता हो तो उसे इंडियन पीनल कोड में दंडित किया जा सकता है, ऐसी उसकी व्यवस्था है । अगर कोई हवाई जहाज का हाइजैकिंग करता है तो उसे ऐंटी हाइजैकिंग कानून के अन्तर्गत सजा दी जा सकती है । तब इस तरह के कानून की क्या आवश्यकता है ? सरकार के लिये यह कोई नई बात नहीं है । कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे

हैं कि सरकार अपने हाथों में अधिक सख्त कानून केन्द्रित करती जा रही है, पाशविक शक्तियों को हाथ में लेती जा रही है। देश की समस्याओं का समाधान करने में जब सरकार असफल रहती है तो वह अथारिटेरियन बन जाती है और अपने हाथ में घातक शक्ति लेकर जनता का दमन करती है और अत्याचारों पर उतारू होकर सत्ता को अपने कब्जे में रखना चाहती है। यह कानून भी उसी तरह का कानून है। सरकार उस के तरकश में यह भी एक तीखा तीर है जिससे हिन्दुस्तान की जनता के बुनियादी अधिकारों पर जबरदस्त रूप से चोट की जाएगी। इसलिये जब सरकार का कहना यह है कि देश के अन्दर जनतंत्र अधिक शक्तिशाली, अधिक व्यापक, अधिक मजबूत होता जा रहा है, जब जनतंत्र देश में अधिक मजबूत और व्यापक हो, उसका विस्तार हो तो जनता के बुनियादी अधिकारों को अधिक से अधिक व्यापक और समृद्ध बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा न करके कुछ पाशविक कानूनों के जरिए जनता के बुनियादी अधिकारों को अपहृत करने की दिशा में इस तरह का कदम उठा रही है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम देश के जनतांत्रिक विकास के लिए कोई स्वस्थ कदम नहीं है और कोई स्वस्थ विकास नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दरबारा सिंह (पंजाब) : वाइस चेयरमेन साहब, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

यह जो प्राइम मिनिस्टर ने इनीशियेटिव लेकर ऐकार्ड किया है, उसमें हमने समझा है कि यह हालात दुरुस्त करने के लिए हुआ है। यहां जो ऐकार्ड हुआ उसमें कुछ धाराएं रखी गई हैं। उसमें से यह निकला है। मैं पंजाब की ही नहीं सारे अवाम की बात करता हूं। मैं टेररिस्ट की बात नहीं करता। अवाम की बात इसलिए करता हूं उनमें एक ऐसी बात है, दे हैव हीव्ड ए साई आफ रिलीफ, उनको आराम आया है। जो झंझट खड़ा था, रोज एजिटेशस होते थे, रोज ऐसे सवाल खड़े किये जाते थे जो देश के हित में नहीं थे उन सब का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश हुई। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अन्दर और बाहर भी इस बात को कहा कि मैं पंजाब की समस्या को हल करना चाहता हूं, मैं असम की समस्या को हल करना चाहता हूं। हमें खुशी होनी चाहिए कि असम और पंजाब दोनों के मसले हल कर दिये गये। यह उनकी अपनी डिटरमिनेशन है, उनकी अपनी अकलमंदी है स्टेट्समैनशिप है। सारे देश भर में उनकी प्रशंसा हुई है। और जो हालात को दुरुस्त करने के लिये मसले खड़े हैं उनको भी दुरुस्त करने की कोशश हो रही है और होती रहेगी। मुझे यह भी कहना है कि यह क्यों आया था। यह इसलिये आया था कि लगातार बेगुनाह आदमियों का खून किया जा रहा था और कोई आदमी भी आगे आने के लिये तैयार नहीं था और पुलिस भी उनको पकड़कर पेश कर सकती थी और कुछ नहीं। जो आदमी एवीडेंस देने वाले थे उन पर गोली चलती थी, उन को मार दिया जाता था। ये हालात ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने इनमें से निकलने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर की स्टेट्समैनशिप की वजह से इस मसले को हल किया गया है। उनकी वजह से ही सारे हालात दुरुस्त होते जा रहे हैं। आम आदमी, जो मासेज में रहने वाला है, खेतों में काम करने वाला है, कारखानों में मजदूर का काम करने वाले हैं, कारखानेदार हैं, सब लोगों ने एक अहसास महसूस किया है कि अब हालात दुरुस्त हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउन्समेंट किया है, बेशक वह एनाउन्समेंट एक इकोनोमी को दुरुस्त करने के लिए हो, कारखानेदार के हक में हो, मजदूरों के हक में हो, जितना पैसा दिया है वह बहुत कम दिया है लेकिन 15 से 30 करोड़ जो दिया है यह माहौल को दुरुस्त करने के लिए है। जो अमेंडमेंट में कहा है वहां ऐसी धारा जोड़ी है जिससे जो कमियां रह गई हैं वह दूर हो सके। हम हाइजैकिंग की बात

[श्री सूरज प्रसाद]

आसानी से कह देते हैं। यहां हमारे पड़ोस में किनारे पर कितने ही हाइजैकर्स बैठे हुए हैं उनको चाय-पानी, अच्छा खाना-पिना सब कुछ दिया जा रहा है। आपके पास कौन सा कानून है जिसकी वजह से आप उनको तावील में ले जाते हैं। कनाडा ने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम टैरेरिस्टों को वापस करें। जर्मनी में पकड़े गए, कनाडा में जाकर उनको छोड़ दिया गया। हम क्या करें। इस का बैकग्राउन्ड हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। केवल अखबारों से पढ़ने से बात नही मिलती। आप वहां जाकर देखिए कि क्या हालत है। मैं यह समझता हूं कि हमें ऐसा जाब्ता बनाना पड़ा क्योंकि सामने आदमी आकर कत्ल करके चला जाता है और छुप जाता है, किसी गुरूद्वारे में छिप जाता है, किसी और जगह छिप जाता है और वहां से निकालना जरा मुश्किल हो जाता तो आप इसके लिए भी चाहते हैं कि वह आर्डिनरी कोर्ट में चला जाए ताकि वहां कोर्ट से छूट कर चला जाए और फिर कत्ल करना शुरू कर दे और घर वापस आ जाए। फिर वही बातें शुरू हो जाए? इसलिए हमने धाराएं निकाली हैं जिसमें आमतौर पर जो केस जा सकते है वे जाएं आर्डिनरी कोर्स में। यह कहा है कि किसी कोर्ट से ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है, न किसी संस्था और न किसी आइडोलोजी के खिलाफ है बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ है जो कत्ल कर चुके हैं, हत्या करी है जिनका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। कातिल का मजहब नही होता है। उसका मजहब कत्ल करना होता है। उसका ताल्लुक चाहे किसी से हो, किसी भी आदमी से हो, किसी पार्टी से हो, उसको आर्डिनरी कोर्ट में ले जाना ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि वे कत्ल करके भाग जाते है। क्या आप चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाय? जो हमारे पढ़े-लिखे वकील है वे जानते हैं कि किस तरह से वे लोग कोर्ट से छूट जाते है। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको आर्डिनरी कोर्ट में ले जाना ठीक नही है। मुझे माफ कीजियेगा, आज ही सुबह हमें खबर मिली है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रेजीडेंट के घर में गोली चली। वे अस्पताल में क्रिटिकल हालत में हैं। लेकिन एक दूसरे आदमी को वहां पर ढ़ेर कर दिया गया और वे भाग गये। क्या आप चाहते हैं कि उनको आर्डिनरी कोर्ट में ले जाया जाय? मैं समझता हूं कि जितने भी आर्डिनरी केसेज हैं उनको अलग किया जाय।

We should appreciate this stand of the Government. We are obliged to the Government that they have brought this amendment for those people who are not of a terrorist type.

जो टेरोरिस्टस भाग जाते हैं उनके लिए स्पैशल कोर्टस का प्रोविजन किया गया है। यहां पर कहा जाता है कि पुलिस मुकाबला करती है। क्या आप चाहते है कि पुलिस मुकाबला न करे? यह भी कहा जाता है कि पुलिस फेक एनकाउन्टर करती है और अपने आप को जखमी कर लेती है। यह क्या बात हुई? यह आप कैसी बात करते है? क्या वे अपने आप पर गोली चला लेंगे?

This is the time that we should support this amendment which has been brought by the Government to separate the terrorists and other activities of the people.

मैं पूरे तौर पर इस बिल की ताईद करता हूं।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill has been brought in pursuance of the Punjab accord. The offences under the Special Courts Act have been limited now to only serious offences of waging war and hijacking. What my learned friend just now said that serious offences are there is not correct. All offences that have been taken out from the Special Courts Act now will be tried by ordinary courts. If the people are killed or people are attacked then this does not come under the provisions of this Act now. Therefore, the impression that they will also be

governed by Special Courts Act is not correct. Today the Act has become a limited one; and ordinary courts will take care of other serious offences.

My hon. friend has already stated that a political solution should be found for Punjab accord. Had the Government taken a political decision earlier as had been recommended by the opposition parties unanimously the blood-bath would not have taken place there. It would have reduced the tension. Mere criminal law or Special Courts is not a substitute towards a political solution. I feel political solution alone is a remedy for political problems.

[**The Deputy Chairman** in the Chair].

When the Act was passed we had criticised. Now, I would like the Home Minister to consider section 12 of this Act wherein it has been provided, I quote: "Notwithstanding anything contained in the Code, the proceedings before a Special Court shall be conducted in camera." Further it was provided that only when public prosecutor applies then the proceedings will be held in the open court. It also provided further that identity and address of the witness will be kept secret. Sir, holding trial in camera is a complete negation of the criminal jurisprudence and is against all principles of the judicial decision. No powers have been given to the accused to apply for having open trial. The second provision which has been provided under Section 20, 111(a) is about "presumption", if it is found at a place where the firearms explosion takes place, the burden of proof will be on him and the offences under Sections 121, 121(a) and 122, offences are still retained in the amended Act. Even though, they were waging war against the Government, there were so many trials in India before independence. Open trials were held and the people were either executed or convicted but waging war has now got a very serious connotation. The principle that open trial does not help either the country or the public opinion is totally wrong and therefore, I take this opportunity to appeal to the Home Minister that Section 12 should be deleted and the principle of open trial is accepted for all offences including heinous offences. In modern heinous offences, open trial helps to create public opinion. It is public opinion and an alert public opinion which has helped bringing about the Punjab record and because of the situation in Delhi and other places where so many explosons took place and because the people did not support such actions—nothing could be done by individual extremists and therefore in a democracy, open trial is a very important insurance for keeping peace and also for creating public opinion and therefore, I suggest to the Hon'ble Minister that these two provisions of presumption and open trial (*Time bell rings*) 111 (a), section 20 be changed and the Ordinary Criminal Procedure code should be made applicable. Now only one point I want to say it has been stated here, criminal conspiracy or an attempt at criminal conspiracy; when under 122 and 123, hijacking will be the only offences. Now hijacking also is a very serious matter and I request the Government to frame more stringent provisions for hijacking offences due to which our country has suffered to a very large extent. With this, I support the Bill.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam Deputy Chairman, I am thankful to the Hon'ble Members who have taken part in this discussion and I think, this is worth noting that all the Hon'ble Members from both the sides have welcomed this measure and they have lent their support. However, some points have been made and it has been emphasized by Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Mohunta, Shri Pyarelal Khandelwal, Shri Satyanarayan Reddy, Shri Suraj Prasad and Shri S. W. Dhabe that the Opposition even at the time when this Bill was brought before the House, when it was passed, even then they say that the Opposition had emphasized that answer to politi-

[Shri Arif Mohd. Khan]

cal problems lies in political solution and negotiation and not in getting this kind of Acts passed Madam, the Government has never denied the importance of trying to find political solution by holding negotiations. In fact, the Government always kept its doors open always extended the invitation to the leaders of the agitation for holding negotiation. Passing laws like the one which we are discussing now never meant that we were not in favour of holding either negotiation or trying to find political solution but well the Government did its best and finally the Government succeeded in bringing the leaders to the negotiating table and an agreement was signed between the Government and the President of the Shiromani Akali Dal. But, at the same time, the Government must have powers to deal with elements who try to take advantage of a situation. If some political demands were being raised, under the garb of the agitation, some elements resorted to extremist activities. They resorted to violence. They made life difficult for many innocent people. The Government was of the view that the Government should be vested with powers so as to deal effectively with the extremist elements. And the purpose of this Act was not to find a solution for the Punjab problem through this measure. The solution was to be found through political means, through negotiations and settlement. But to deal with those elements who were trying to resort to violence, who were trying to make a mockery of the law and order situation, we felt that this was essential at that time. And now an agreement has been signed and, Madam, I would like to refer to one clause of the agreement about the disposal of pending cases. It says:

"The notifications applying the Armed Forces (Special Powers) Act to Punjab will be withdrawn. The existing Special Courts will try only cases relating to the following types of offences: waging war and hijacking."

In pursuance of this agreement, we have come with this Bill. Once again I would like to thank the hon. Members for the support which they have extended to this Bill.

Shri Khandelwal had specifically asked about the cases which were registered under this Act. Under section 302 of the IPC, 605 cases were registered. There were 1,685 accused. Under section 307, IPC, there were 368 cases; under section 392, 75 cases; under section 395, 35 cases; under section 436, 67 cases; under section 456, 13 cases; under section 124, 6 cases; under other IPC sections, 330 cases; under the Arms Act, 2,372 cases, under other Acts, 25 cases.

Madam, many cases have been disposed of. The total number of cases which have been disposed of is 3,654.

SHRI S. W. DHABE: How many are pending?

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I have given you the total number. And 3,654 have been disposed of. So the pending number can be worked out. In any case, these pending cases will be transferred to ordinary courts. Since the Act will not apply now to these sections under IPC which I have enumerated, they will be transferred to the ordinary courts.

Madam, I think that since almost all the hon. Members of the House have extended their support to this Bill, I need not dilate on this subject any more. Once again I would like to thank the hon. Members for the support which they have given to this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Madam I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

---

5 P.M.

ANNOUNCEMENT REGARDING STATEMENTS BY MINISTERS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make an announcement that we were to have two statements by Ministers on railways and petroleum. But because of the important discussion we are going to take up on the situation in South Africa, the statements will be made tomorrow. The Prime Minister will intervene on the discussion on the racial riots in South Africa at 5-20 p.m. today.

The discussion will be initiated by you, Mr. Jaswant Singh, but before that the Minister will make a statement and in the light of his statement you might get some more talking points as they have done in Lok Sabha.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): I welcome the opportunity of speaking after the Minister's statement it will admirably suit my points. But I would take note of only one part of your remark and it is that just because Lok Sabha did it, we might do likewise. . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not what I meant. We are doing it on our own, not because Lok Sabha did it. The idea is the Minister's statement will give you a better opportunity.

SHORT DURATION DISCUSSION ON RACIAL RIOTS IN SOUTH AFRICA AFFECTING THE PEOPLE OF INDIAN ORIGIN

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KHURSHID ALAM KHAN): Madam Deputy Chairman, the despicable system of Apartheid must be the starting point of any discussion of the South African situation. Apartheid was devised by the White minority to perpetuate its supermacy over other communities, who form 85 per cent of the population of South Africa. The United Nations has rightly described Apartheid as a crime against humanity. The rights and freedoms defined in the United Nations Declaration of Human Rights are denied to non-Whites. Colour discrimination extends not only to employment and habitation, but to public transport, public places like cinemas, museums, sports stadia, restaurants and parks and gardens. People of different races may not even be carried to hospital in the same ambulance. Political parties serving the interests of the oppressed majority, in particular, the African National Congress and also the Pan Africanist Congress, are banned and have to operate from exile.

Among the many reprehensible features of Apartheid is the creation of the so-called "homelands" or "Bantustans" for the Africans. Though they comprise 73 per cent of the total populaton, the Bantustans have been allocated only some 13.7 per cent of the total area of the country. These are among the poorest areas which contain no major known deposits of minerals, no major industries or sea ports. Millions of Blacks and coloureds are permitted to live and work in "White" areas but only so long as this source of cheap labour is required by the ruling minority. Africans might be thrown out at any time if they are considered surplus to the requirements of White employers or have become old or sick. These Black residents